Cost overruns due to Delay in Project

3920. MD. SALIM:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minsiter of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the reasons for the delay in commissioning of various important projects in the States which caused cost overrun; and

(b) whether at the time of planning this aspect of cost overrun is taken into account?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING & PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) As on 1.1.1997, there were 410 central sector projects costing Rs. 20 crores and above on the monitor of DPI, which were under implementation in various states. Out of these 410 projects, 189 projects were having cost overrun of which 132 were also running behind the original approved schedule. The main reasons of delay in commissioning of projects which result in cost overrun are delay in acquisition of forest and non-forest land, fund constraints, delay by vendors, contractors, adverse law and order situation in certain parts of the country, etc., with time overrun the cost goes up on account of inflation, exchange rate variation, interest during construction, etc.

(b) At the time of original project planning the cost estimates are based on the prevailing prices. At the stage of approval of revised cost estimates, the adverse factors are taken into account.

मध्य प्रदेश और गुजरात में पिछड़े जिलों की पहचान करने का नया मापदण्ड

3921. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:**

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछड़े जिलों की पहचान के लिए कोई नया मापदण्ड बनाया है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई समिति गठित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने गुजरात और मध्य प्रदेश में कुछ जिलों को पिछड़े जिलों के रूप में घोषित करने का निश्चय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपरोक्त समिति ने इन राज्यों में कुछ जिलों के रूप में घोषित करने के लिए अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) से (च) जी, नहीं। किसी क्षेत्र विशेष की आयोजना तथा विकास और इस प्रयोजनार्थ निधियों का आवंटन मूलत: संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। योजना आयोग ने किसी जिले को पिछड़ा घोषित करने की दृष्टि से कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया है। बहरहाल, ग्रामीण विकास तथा रोजगार मंत्रालय में 100 सर्वाधिक पिछड़े तथा गरीब जिलों की पहचान के निमित्त एवं विभिन्न राज्यों में ऐसे जिलों का पता लगाने की दृष्टि से तथा "ढांचागत विकास" को यथेष्ट रूप में परिभाषित करने हेतु एक समिति का गठन किया है। 26 फरवरी, 1997 को समिति का गठन किया गया था और इसे दो माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

Promotion of Research on the Industry in Maharashtra

3922. PROF. RAM KAPSE: Will the Minsiter of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether CSIR have entered into any collaboration for promotion of research relevant to industry in Maharashtra;

(b) if so, the details of the projects, alongwith the results obtained till date; and

(c) if not reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) and (b) CSIR enter into collaboration with industry for joint undertaking of research for applications/use by the industry. Some of the significant